

**न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर**  
(निर्णय बर्डजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-08/2010/भीलवाड़ा (2010/00005)

1. देवीलाल पिता कुशल बागरिया निवासी भोपालपुरा, भीलवाड़ा

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मधु पत्नी प्रताप सिंह देवडा, निवासी तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. चण्डीप्रसाद पिता प्रहलाद खण्डेलिया निवासी गांधीनगर, भीलवाड़ा
3. सुनील पिता हरनारायण ओझा
4. हरिश पिता हरनारायण ओझा
5. नीरज पिता हरनारायण ओझा  
निवासी बी-3, बसन्त विहार, भीलवाड़ा
6. अंकुर पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी काशीपुरी, भीलवाड़ा
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

रेस्पोंडेंट्स

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 12.11.2009 अंतर्गत प्रकरण संख्या 04/2009.**

**उपस्थित:-**

1. श्री ईश्वर देवडा, वकील अपीलांट ।
2. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत अभिभाषक रेस्पों सं0 1
3. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पों संख्या 7
4. राजकीय अभिभाषक श्री बी0एस0 शेखावत
5. रेस्पों सं0 2 एवं 6 अनुपस्थित

(2) अपील संख्या :-56/2010/भीलवाड़ा (2010/00003)

1. श्रीमती मधु पत्नी प्रताप सिंह देवडा, निवासी तहसील व जिला भीलवाड़ा

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
3. देवीलाल पिता कुशल बागरिया निवासी भोपालपुरा, भीलवाड़ा

4. चण्डीप्रसाद पिता प्रहलाद खण्डेलिया निवासी गांधीनगर, भीलवाडा
5. सुनील पिता हरनारायण ओझा
6. हरिश पिता हरनारायण ओझा
7. नीरज पिता हरनारायण ओझा  
निवासी बी-3, बसन्त विहार, भीलवाडा
8. अंकुर पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी काशीपुरी, भीलवाडा

रेस्पोंडेंट्स

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा दिनांक 12.11.2009 अंतर्गत प्रकरण संख्या 04/2009.**

**उपस्थित:-**

1. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, वकील अपीलांत ।
2. राजकीय अभिभाषक श्री बी0एस0 शेखावत
3. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पों संख्या 2
4. रेस्पों सं0 3 एवं 8 अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक :- .....

अपीलांत ने दो अलग-अलग अपीलें विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं । दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे । xx

- 1- दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती मधु पत्नी प्रतापसिंह देवडा द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा स्वीकृत नामा0सं0 2894 दिनांक 22.04.2004 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किये कि जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 वर्ष 1988-89 में ग्राम भीलवाडा, पटवार हल्का भीलवाडा में स्थित आराजी ख0नं0 2411, 2418, 2419, 2420 कुल किता 4 कुल रकबा 3.14 बीघा रेस्पोंडेंट सं0 3 देवीलाल पुत्र कुशल बागरिया के नाम दर्ज थी, जिसने अपनी उक्त कृषि भूमि को आवासीय योजना में परिवर्तित करने हेतु वर्ष 1988-89 में विवादित आराजीयात को रेस्पों सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा को समर्पित करते हुए उक्त विवादित आराजीयात का आवासीय प्रयोजन हेतु ले-आउट प्लान नगर विकास न्यास, भीलवाडा में पेश कर वर्ष 1988-89 में प्लान स्वीकृत करवा लिया। रेस्पों सं0 3

देवीलाल ने विवादित आराजी में 39 आवासीय भूखण्ड काटकर विभिन्न व्यक्तियों को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.07.1999 के परिपत्र अनुसार विक्रय कर, विक्रय राशि प्राप्त कर ली, तभी से केता व्यक्तियों ने अपने भूखण्डों पर कब्जा कर निर्माण कार्य समपन्न करवा लिया। इस प्रकार वर्ष 1988-89 के बाद से रेस्पों सं० 3 देवीलाल का विवादित आराजीयात पर कोई हक व स्वामित्व शेष नहीं रहा। आवासीय योजना के 39 भूखण्डों में से भूखण्ड सं० 6 नपती 30 बाई 64 फीट कुल 1920 वर्गफीट का अपीलांट श्रीमती मधु ने रेस्पों सं० 3 देवीलाल से दिनांक 02.06.1988 को 2500/- रुपये अदा करके क़य कर कब्जा प्राप्त कर लिया। अपीलांट श्रीमती मधु ने उक्त भूखण्ड सं० 6 को नियमन करवाने हेतु रेस्पों सं० 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा के यहां पत्रावली आवेदन पत्र सं० नियमन/2000/8207 दिनांक 13.06.2000 को पेश कर नियमानुसार राशि नगर विकास न्यास, भीलवाडा के यहां जमा करवा दी। तब से लेकर आज तक अपीलांट श्रीमती मधु को नियमन संबंधी आवेदन रेस्पों सं० 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा के यहां विचाराधीन चला आ रहा है। इसी दौरान नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने उक्त विवादित आराजीयात का ले-आउट प्लॉन पास कर लेने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उक्त कृषि भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही अवैध, जो प्रारंभ से ही शून्य कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त अवाप्ति कार्य को निरस्त कर दिया। इसके बाद रेस्पों सं० 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने दिनांक 20.04.02 को बैठक आयोजित कर जिला कलक्टर, भीलवाडा से उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु राय मांगी गई, जिस पर जिला कलक्टर ने अपने पत्र क्रमांक एफ/34-6 सा शा/2001-02 दिनांक 09.03.02 द्वारा आदेश दिया गया कि विवादित आराजीयात पंचवटी विस्तार योजना में अब किसी प्रकार कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा वहां प्लॉट कटे हुये हैं। अतः 90बी की कार्यवाही कर भूमि का अपने नाम दर्ज करावें। जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 09.03.02 के आदेश की पालना में रेस्पों सं० 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने तहसीलदार, भीलवाडा को एक आदेश दिनांक 16.12.02 प्रेषित कर आदेश जारी किया कि पंचवटी विस्तार योजना में कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें। उक्त आदेश आज दिन तक प्रभावी है। इस प्रकार पंचवटी विस्तार योजना की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन पर रोक दिनांक 16.12.02 से जारी की हुई थी। विवादित आराजीयात के संबंधित भूखण्ड के मालिकों से नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने वर्ष 2000 में 90बी के तहत नियमन कर आवासीय पट्टे जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हुये थे। आवासीय क्षेत्र का ले-आउट का प्लॉन पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। इन सभी कारणों से नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने अपनी बैठक दिनांक 20.04.02 एवं 26.04.03 में निर्णय लिया कि पंचवटी विस्तार योजना में स्थित भूमि पर काफी विकास किया जा चुका है, जिस कारण नियमन शुल्क के

साथ विकास शुल्क 50 रुपये अलग से वसूल किया जाकर नियमन किया जावे। तत्पश्चात रेस्पों सं० 2 नगर विकास न्याय, भीलवाडा द्वारा गैरकानूनी रूप से दिनांक 20.04.04 को पत्र क्रमांक भूमि/04/1617 जारी कर ग्राम भीलवाडा की आराजी नम्बर 2418, 2419, 2420, 2411 कुल 3.14 बीघा को मूल खातेदार के नाम रद्दोबदल करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जिसका रेस्पोंडेंट देवीलाल द्वारा गलत अर्थ निकालते हुये एवं उच्च अधिकारी के रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करने के आदेश होते हुए भी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगती कर गलत एवं अवैध आदेश जारी करवा कर पुनः रिवर्ट बैक कर रेस्पों सं० 3 देवीलाल ने अपने नाम नामा० सं० 2894 दिनांक 22.04.2004 स्वीकृत करवा लिया। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट श्रीमती मधु ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। अधी०न्याया (जिला कलक्टर, भीलवाडा) ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2009 द्वारा अपील खारिज फरमा दी। अधी०न्याया० के निर्णय दिनांक 12.11.2009 से अप्रसन्न होकर यह दोनों अपील प्रस्तुत की गई है। xx

- 2- दोनों अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट्स के नोटिस तामील होने अथवा उपस्थित होने एवं अधी०न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पों की बहस सुनी गई। xx
- 3- सर्वप्रथम हम अपील संख्या 56/2010 (2010/00003) के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थीया ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।
- 4- अपीलान्ट की बहस गुणावगुण पर सुनी गई। अपील संख्या 08/2010 (2010/00005) में अपीलान्ट अभि० श्री ईश्वर देवडा ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधी०अपीलय न्याया० एक ओर तो नामा० को विधिसम्मत मानता है व रेस्पों सं० 1 को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानता है। अधी०न्याया० द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि “अपीलार्थीयां (रेस्पों सं० 1) की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित आराजी भू-भाग में भूखण्ड खरीद करने के उपरांत उसकी ओर से सक्षम अधिकारी के यहां कृषि भूमि को अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्य परिवर्तन कराने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया हो।” अर्थात रेस्पों सं० 1 द्वारा तथाकथित इकरार नामे को आधार बनाते हुए बिना किसी साक्ष्य सबूत के अनुतोष चाहा है, जिसे न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज किया गया किन्तु दूसरी ओर उसी न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण वर्णित किये अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पों सं० 1 के स्वामित्व निर्धारण तक प्रश्नगत

भूमि के संबंध में नियमन एवं संपरिवर्तन कार्यवाही नहीं करने का आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अविधिक होकर निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधी०न्याया० का निर्णय इस हद तक निरस्त फरमाया जावे। xx

- 5- अपी० अभि० की उक्त बहस के जवाब में रेस्प० अभि० ने कथन किया कि अधी०न्याया० द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्वामित्व निर्धारण तक प्रश्नगत भूमि के संबंध में नियमन एवं संपरिवर्तन कार्यवाही नहीं करने का आदेश हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु किया है जो पूर्ण रूप से न्यायालय के विवेकाधिकार के तहत होकर वैधानिक है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जाकर इस हद तक अधी० न्याया० का निर्णय यथावत रखा जावे। xx
- 6- अपील संख्या 56/2010 (2010/00003) के अपीलांत अभि० श्री गजेन्द्रसिंह राजावत ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधी०न्याया० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रश्नगत नामा० के वैधता को निर्णित करते समय इस बिन्दु को निर्णित करने का अधिकार नहीं था कि अपी० द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीदा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक था। अधी०न्याया० द्वारा नगर विकास न्यास एवं आवासन विभाग, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.07.1999 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया जबकि रेस्प०सं० 3 अपंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा भूखण्ड विक्रय करने हेतु स्वतंत्र था और ऐसे भूखण्डों के लिए पंजीयन होना आवश्यक नहीं था। नामा० में लिप्त आराजी भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिग्रहण नहीं की गई थी बल्कि रेस्प०सं० 3 ने समर्पित की थी। भूमि अर्जन अधिनियम के तहत ऐसे कोई नोटिफिकेशन या आदेश जारी नहीं किया गया था जिसके तहत भूमि अधिग्रहण की गई हो। ऐसी स्थिति में धारा 144 सी०पी०सी० के प्रावधान लागू होना मानते हुए नामा० सं० 2894 को सही स्वीकृत मानकर उसकी पुष्टि करना विधि विरुद्ध है। अधी०न्याया० को यह देखना था कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कौन से आदेश को अपास्त किया, जिसके आधार पर विवादित नामा० स्वीकृत किया गया है। जब रेस्प०सं० 3 ने नामा० में लिप्त आराजी में से भूखण्ड अपीलांत को विक्रय कर कीमत प्राप्त कर ली है। उसके बाद अपीलांत का विवादित आराजी में हित निहित हो गया है। अगर अपीलांत विवादित आराजी में थोड़ा सा भी हित रखती है तो उसे अपील करने का पूर्ण अधिकार है। अधी०न्याया० द्वारा अपीलांत का लोकस स्टेण्डाई नहीं मानकर अवैधानिकता बरती है। अधी०न्याया० का यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि अपीलांत ने भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने एवं अवाप्ति व नगर सुधार न्यास का आदेश अथवा अपीलांत द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। जबकि रेस्प०सं० 2 ने अधी०न्याया० के समक्ष यह सभी मिनिट्स प्रस्तुत किये हैं जिनसे नामा० में लिप्त आराजी रेस्प०सं० 2 में निहित हो गई एवं पंचवटी कॉलोनी के विस्तार में सम्मिलित कर दी गई।

अधी०न्याया० द्वारा नामा० में लिप्त आराजी को एक ओर तो विवादस्त मानकर रेस्पो०सं० 2 को निर्देश दिये है कि वह रूपान्तरण संबंधी या पट्टा संबंधी कार्यवाही नहीं करें, वही दूसरी ओर रेस्पो०सं० 3 के पक्ष में स्वीकृत नामा० को पुष्ट कर रहे है, जो अपने आप में विरोधाभाषी है। जब रेस्पो०सं० 3 द्वारा भूमि को भूखण्ड काटकर हस्तान्तरित किया जा चुका है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो चुके है, भले ही विक्रय पत्र अपंजीकृत क्यों नहीं हो। तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामा० तस्दीक किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उपरोक्त आधारों पर अपीलाधीन नामा० निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। xx

7- विद्वान वकील रेस्पो० 1 व 2 ने अपील के जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी भू-भाग को नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने अवाप्त कर अपने पक्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया गया लेकिन भूमि अवाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत होकर अवाप्ति कार्यवाही के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। अधी०न्याया० द्वारा वैधानिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट खारिज फरमाई जावें। xx

8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी०न्याया० के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रकरण में गुणावगुण पर अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी भू-भाग को नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने अवाप्त कर अपने पक्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया गया लेकिन भूमि अवाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत होकर अवाप्ति कार्यवाही के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। जब नीचे की अदालत के किसी आदेश को उपर के न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में अंकित प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख में नीचे की अदालत के द्वारा दिये गये आदेश के पहले की जो स्थिति रेकार्ड की बनी हुई थी वहीं स्थिति रेकार्ड पर वापस स्थापित करना होता है और यहां पर भी यही स्थिति है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार कोई भी अचल सम्पत्ति जिसका कि विक्रय 100 रुपये की मालियत से अधिक का किया गया है तो उसका विहित नियमों के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक है एवं धारा 49 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी अचल सम्पत्ति के लिए विक्रय विलेख जो अपंजीकृत है, ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। ऐसा विक्रय विलेख उक्त नियमों के अन्तर्गत वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। अपीलांट ने भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने एवं अवाप्ति व नगर सुधार न्यास का आदेश अथवा अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। उक्त आधारों पर अधी०न्याया० द्वारा अपीलांट का लोकस स्टेण्डाई नहीं मानते हुए अपीलाधीन नामा० को यथावत

रखने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। हम अधीन न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष से हम सहमत हैं कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु हक अधिकार व स्वामित्व को तय करने का है और इसके लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है, जिससे वादग्रस्त आराजी भू-भाग में नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा भूमि अवाप्ति कार्यवाही से पहले जिन व्यक्तियों ने भू-खण्ड खरीद किये हैं व अवाप्ति कार्यवाही आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात् जिन व्यक्तियों ने पंजीकृत विक्रय विलेखों से भूमि को खरीद किया है। उनके पक्ष में नगर विकास न्यास, भीलवाडा तब तक नियमन अथवा सम्यपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं करें जब तक उपरोक्त हितबद्ध क्रेतागण द्वारा सिविल न्यायालय से अपना हक व स्वामित्व तय नहीं करावा लेते। इस प्रकार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2009 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। xx

- 9- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीलें खारिज करना तथा अधीन अपीलीय न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2009 यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

**-:क्रियात्मक आदेश:-**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 08/2010 (2010/00005) बउनवानी देवीलाल बनाम श्रीमती मधु व अन्य, अपील संख्या 56/2010 (2010/00003) बउनवानी श्रीमती मधु बनाम सरकार व अन्य को खारिज किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2009 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे।

(सत्तार खान)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
अजमेर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,  
अजमेर

